

Seventeenth Series, Vol. XXII No. 3

Thursday, February 02, 2023

Magha 13, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES
(Original Version)

Eleventh Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXII contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan
Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Thapliyal
Joint Director

Meenakshi Rawat
Anil Kumar Chopra
Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXII, Eleventh Session, 2023/1944 (Saka)
No. 03, Thursday, February 02, 2023/ Magha 13, 1944 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	
Welcome to Parliamentary Delegation from the Republic of Zambia	8
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 1	9-10
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 2 to 20	11-90
Unstarred Question Nos. 1 to 230	91-748

PAPERS LAID ON THE TABLE	750-756
ASSENT TO BILLS	757
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
39 th Report	758
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE	
337 th and 338 th Reports	758
MATTER UNDER RULE 377	759-776
(i) Need to establish a Dairy Research Institute and Dairy Training Centre in the Salempur Parliamentary Constituency Shri Ravindra Kushawaha	759
(ii) Regarding establishment of PM Shri Schools in Pali Parliamentary Constituency Shri P. P. Chaudhary	760
(iii) Need to develop 'Pratap Circuit' connecting the places associated with Maharana Pratap Sushri Diya Kumari	761
(iv) Need to develop religious places under Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme Shri Nayab Singh Saini	762
(v) Need to enhance the income-ceiling criteria for SC and ST students for pre-metric scholarship Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki	763

- (vi) Need to ensure quality and maintenance of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Hardoi district as per specified norms
Shri Ashok Kumar Rawat 764
- (vii) Regarding construction of Chatra-Gaya and Barwadih-Chirmiri Railway line projects
Shri Sunil Kumar Singh 765
- (viii) Regarding technical glitches in computer software utilized for the Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) in Latur district, Maharashtra
Shri Sudhakar Tukaram Shrangare 766
- (ix) Regarding grant of approval to DPR for construction of Rahul Utai River dam in Kalahandi district
Shri Basanta Kumar Panda 767
- (x) Need to set up a Buddhist Culture and Heritage Conservation Centre and also a Convention Centre in Siddharthnagar district
Shri Jagdambika Pal 768
- (xi) Regarding crop insurance claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shri Rahul Kaswan 769
- (xii) Regarding establishment of Post Office Passport Seva Kendra in Guna and Shivpuri in Madhya Pradesh
Shri Krishnapalsingh Yadav 770

- (xiii) Regarding to grant environment clearance to development projects in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency
Shri Ashok Mahadeorao Nete 771
- (xiv) Regarding inclusion of femicide as an offence under the Indian Penal Code
Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian 772
- (xv) Regarding not to ban film/documentary on ideological differences
Prof. Sougata Ray 773
- (xvi) Regarding release of coal levy to states
Shri Bhartruhari Mahtab 774
- (xvii) Regarding laying of sewer lines under AMRUT Yojana in Jaunpur, Uttar Pradesh
Shri Shyam Singh Yadav 775
- (xviii) Regarding water pollution in the backwaters of Khadakwasla dam
Shrimati Supriya Sadanand Sule 776

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	765
Member-wise Index to Unstarred Questions	766-771

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	772
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	773

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, February 02, 2023/ Magha 13, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

**WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION
FROM THE REPUBLIC OF ZAMBIA**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से और इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत के दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री नेली बूटेटे मूटी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।

जाम्बिया का संसदीय शिष्टमंडल बुधवार, 1 फरवरी, 2023 को भारत पहुँचा और शिष्टमंडल के सदस्य अब विशेष दीर्घा में आसीन हैं। वे भारत से वापसी के पहले दिल्ली के अतिरिक्त शनिवार, 4 फरवरी, 2023 को आगरा का भी भ्रमण करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। हम जाम्बिया के शिष्टमंडल के माध्यम से जाम्बिया गणराज्य के संसद सदस्यों, वहाँ की सरकार और मित्रवत् जनता को बधाई और शुभकामनायें देते हैं।

11.02hrs**ORAL ANSWER TO QUESTION**

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1, श्रीमती पूनमबेन माडम ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न काल है और प्रश्न काल महत्वपूर्ण होता है । प्रश्न काल चलना चाहिए । सभी विधान मंडलों के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की गई थी । सभी माननीय विधान सभा अध्यक्षां ने कहा है कि प्रश्न काल स्थगित नहीं होना चाहिए ।

... (व्यवधान)

11.03 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, Sushri Mahua Moitra and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

(Q. 1)

श्रीमती पूनमबेन माडम : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी ।

... (व्यवधान) हम सभी जानते हैं कि पानी की सबसे ज्यादा खपत सिंचाई के रूप में होती है ।

... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है । ... (व्यवधान) हम

सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माइक्रो इरीगेशन को बढ़ावा देते हैं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सदन को चलाना नहीं चाहते हैं । आप सदन की मर्यादा नहीं रखना चाहते हैं । सदन चले, आप अपने बुनियादी सवालों को उठाएं, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूँगा ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कृपया अपनी सीट पर जाइए ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिना तथ्यों के कोई बात मत कीजिए । कृपया, अपनी-अपनी सीट्स पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाकर बैठिये ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है । जब माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के द्वारा सरकार से जवाब पूछते हैं, तो उन प्रश्नों के जवाब से समस्याएँ हल होती हैं, समाधान होता है ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप सब अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

... (व्यवधान)

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 2 to 20
Unstarred Question Nos. 1 to 230)
(Page No. 11-748)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

11.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

... (व्यवधान)

14.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

... (व्यवधान)

14.0½ hrs

At this stage, Prof. Sougata Ray, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8495/17/23]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8495-A/17/23]

- (3) वर्ष 2023-2024 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8496/17/23]

... (व्यवधान)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1032(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 8496-A/17/23]

- (2) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8497/17/23]

(3) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, बट्टी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, बट्टी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8498/17/23]

(4) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर – पुडी (विशाखापतनम) के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर – पुडी (विशाखापतनम) के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8499/17/23]

(5) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8500/17/23]

(6) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, दुर्ग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8501/17/23]

(7) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, कानपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8502/17/23]

(8) (एक) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8503/17/23]

(9) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8504/17/23]

... (व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): माननीय सभापति जी, मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2022-2023 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 8505/17/23]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गुजरात मेट्रो रेल लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8506/17/23]

- (ख) (एक) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8507/17/23]

- (ग) (एक) मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुम्बई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8508/17/23]

(2) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8509/17/23]

(3) (एक) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8510/17/23]

(4) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8511/17/23]

... (व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): माननीय सभापति जी, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 8512/17/23]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला): माननीय सभापति जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
2. चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8513/17/23]

14.03hrs**ASSENT TO BILLS**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table the following three Bills passed by the Houses of Parliament during the Tenth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 08th December, 2022: -

- (i) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022;
- (ii) The Appropriation (No. 4) Bill, 2022; and
- (iii) The Appropriation (No.5) Bill, 2022.

I also lay on the Table a copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of following five Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

- (i) The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2022;
 - (ii) The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022;
 - (iii) The New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022;
 - (iv) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2022; and
 - (v) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022.
-

... (व्यवधान)

14.03½hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

39th Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND

MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I rise to present the

Thirty-ninth Report of the Business Advisory Committee.

... (व्यवधान)

14.04hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM

AND CULTURE

337th and 338th Reports

श्री प्रिंस राज (समस्तीपुर) : माननीय सभापति जी, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 317वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 337वां प्रतिवेदन ।
- (2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 338वां प्रतिवेदन ।

14.04½hrs**MATTERS UNDER RULE***

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन माननीय सदस्यों के नोटिस स्वीकृत हुए हैं, वे उन्हें कृपया सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

... (व्यवधान)

(i) Need to establish a Dairy Research Institute and Dairy Training Centre in the Salempur Parliamentary Constituency.

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया-बलिया सहित पूरे पूर्वांचल के लोगों की आय कृषि व पशुपालन पर आधारित है, पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि करने हेतु डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन दोगुना और खाद्य सुरक्षा को आत्मनिर्भर एवं आत्म संपन्न बनाने के साथ-साथ रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न करने हेतु पशुपालन को व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग से जोड़ना अत्यंत लाभप्रद होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर में खासकर देवरिया, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ सहित बिहार के 2 जिले सिवान और गोपालगंज पूर्णतः कृषि एवं पशुपालन के अनुकूल हैं, यहां व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग की असीम संभावनाएं हैं परंतु समुचित प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक मार्ग निर्देशन प्राप्त न होने के कारण पशुपालकों एवं किसानों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया-बलिया में डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने तथा व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण केंद्र विकसित कराने की कृपा करें, जिससे यहां के पशुपालकों एवं किसानों की आय में दोगुना वृद्धि हो, प्रदेश में डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन दोगुना हो, तथा खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भर आत्म संपन्न बने, रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न हो।

* Treated as Laid on the Table.

**(ii) Regarding establishment of PM Shri Schools in Pali
Parliamentary Constituency.**

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): आज हमारे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की निराशाजनक गुणवत्ता से सभी अवगत हैं। यहाँ तक की देश के अधिकांश निजी स्कूल भी कमोबेश सत्तर के दशक में तैयार शिक्षा के पैटर्न का ही पालन कर रहे हैं। इस विषय पर मैं शिक्षा क्षेत्र के सुधार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ। दूरदर्शी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर ही न रुकते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की है जो अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं, शिक्षण रणनीतियों और तकनीकी प्रगति के माध्यम से बाकी क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करेगी। 27,360 करोड़ रुपये की लागत से 'पीएम श्री स्कूल' नाम से देशव्यापी केंद्र प्रायोजित स्कूलों का शुभारंभ करके और अगले 5 वर्षों में 14500 से अधिक स्कूलों को कवर करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विलक्षण नेतृत्व का एक और उदाहरण पेश किया है।

मुझे आशा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ-साथ देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, सभी सदस्य इस योजना से संबंधित सभी मामलों में केंद्र सरकार के साथ पीएम श्री स्कूलों की स्थापना को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करेंगे।

मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र पाली की प्रत्येक विधानसभा में कम से कम एक-एक 'पीएम श्री स्कूल' का चयन करने की कृपा करें।

(iii) Need to develop 'Pratap Circuit' connecting the places associated with Maharana Pratap.

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद के अंतर्गत प्रताप सर्किट विकसित करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। वीर योद्धा महाराणा प्रताप मेवाड़ एवं राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए पूजनीय हैं। मेवाड़ में आने वाला हर पर्यटक महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थलों का दर्शन लाभ लेना चाहता है और उनके जीवन में हुए संघर्षों को समझना चाहता है। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कुम्भलगढ़, हल्दीघाटी और दिवेर दुर्ग आदि बहुत से स्थल आते हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न सर्किटों के माध्यम से पर्यटन एवं दर्शनीय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इसी तर्ज पर महाराणा प्रताप और मेवाड़ के अन्य शूरवीरों से सम्बंधित त्याग, बलिदान, उनकी जन्मस्थली-कर्मस्थली, वहां के गढ़ों, किलों, धरोहरों एवं पवित्र रणभूमि हल्दीघाटी जैसे स्थलों को प्रताप सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि मेवाड़ क्षेत्र के विकास एवं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के मूल्यों के सम्मान हेतु प्रताप सर्किट के रूप में योजना बनाकर महाराणा प्रताप से सम्बंधित विभिन्न स्थलों को विकसित किया जाए।

(iv) Need to develop religious places under Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme.

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): मैं माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का ध्यान गीता उपदेश नगरी कुरुक्षेत्र की ओर केन्द्रित करना चाहता हूँ कि प्रसाद योजना जो भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत धार्मिक पर्यटन के लिए प्राथमिकता नियोजित और व्यवस्थित तरीके से तीर्थ स्थलों का विकास और सौंदर्यीकरण करना था। हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले में माता मनसा देवी को समर्पित एक महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर माना जाता है, वहीं नड्डा साहेब गुरुद्वारा शिवालिक तलहटी में घघर नदी के तट पंचकूला में स्थित गुरुगोविंद से सम्बंधित सिख समुदाय का धार्मिक स्थल है जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ एवं माथा टेकने आते हैं तथा आदि बट्टी हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित वन क्षेत्र है तथा यहाँ विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी है जहाँ हरियाणा सरकार ने डैम बनाकर सरस्वती हेरिटेज बोर्ड भी बनाया है। इन सभी स्थलों को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाए एवं इनका सौंदर्यीकरण किया जाए।

(v) Need to enhance the income-ceiling criteria for SC and ST students for pre-matric scholarship.

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के शिक्षा के लिए उनको जो प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है उसमे आज भी उनकी पारिवारिक वार्षिक आय की लिमिट 2.5 लाख रुपये है । अभी तक सरकार द्वारा कई पे कमीशन लागू किए गए हैं जिसके बाद एक चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी की आय भी 2.5 लाख से अधिक हो जाती है जिससे उन छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है तथा वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं । अतः महोदय जिस प्रकार से ओबीसी छात्रों के लिए उनकी पारिवारिक आय को 8 लाख किया गया है उसी प्रकार मेरा सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए भी यह लिमिट 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जाए ताकि कोई भी छात्र प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप से वंचित न रहे व अच्छी शिक्षा प्राप्त कर भविष्य में राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सके ।

(vi) Need to ensure quality and maintenance of roads under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Hardoi district as per specified norms.

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उत्तर प्रदेश) के जनपद हरदोई में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से कराये जा रहे सड़क निर्माण पैकेज संख्या यू पी 33175, 33212, 33215, 33216, 33217, 33218, 33219, 33221, 33222 एवं 33223 में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार कार्य नहीं कराए जा रहे हैं।

अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद हरदोई के अंतर्गत उपयुक्त कार्यों को गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप कराए जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

**(vii) Regarding construction of Chatra-Gaya and Barwadih-Chirmiri
Railway line projects.**

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सर्वप्रथम मैं चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि रेल मंत्रालय ने चतरा- गया नई रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही बरवाडीह - चिरमिरी (अंबिकापुर) नई रेल लाइन परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने हेतु स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। चतरा - गया नई रेल लाइन परियोजना के लिए रेलवे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। इस रेल लाइन के साथ-साथ टोरी - चतरा - गया सेक्शन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू करने का प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द चतरा- गया नई रेल लाइन का शिलान्यास किया जाए और इस रेल लाइन के कार्य को अति तीव्रता से करने के पर्याप्त बजट आवंटन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। बरवाडीह - चिरमिरी (अंबिकापुर) रेल लाइन परियोजना झारखंड प्रदेश के चतरा लोकसभा क्षेत्र में आजादी से पूर्व यह रेल लाइन प्रस्तावित थी। इस नई रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान - निर्धारण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्च 2022 में स्वीकृत किया गया था। जोन बिलासपुर में परियोजना के पुनर्जीवित होने से झारखंड एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लोगों में अपार हर्ष है। अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि आजादी से पूर्व की प्रस्तावित बरवाडीह चिरमिरी रेल लाइन को एक तय समय में पूरा करने नियमित निगरानी तंत्र में शामिल कर दिशा में ठोस कदम उठाएं।

(viii) Regarding technical glitches in computer software utilized for the Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen) in Latur district, Maharashtra.

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कम्प्यूटर साफ्टवेयर में कतिपय तकनीकी खराबियों के कारण काफी समय से योजना के अधीन योग्य व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे संबंधित अधिकारियों से पता लगा है कि साफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में योग्य दावेदारों के आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरे लातूर जिले में योजना के तहत 152079 आवेदनों में से कम्प्यूटर से बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों अर्थात् 29276 अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए हालांकि योजना के दिशा निर्देशों के तहत इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी आवास के लिए सभी तरह की पात्रता रखते हैं। राज्य स्तर के अधिकारी साफ्टवेयर में हुई इस तकनीकी खराबी को ठीक करने में असमर्थ हैं। बड़ी संख्या में योग्य व पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकार होने के कारण यहां आम जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं तथा साफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को शीघ्रातिशीघ्र ठीक किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अधीन पात्र सभी उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

**(ix)Regarding grant of approval to DPR for construction of Rahul
Utai River dam in Kalahandi district.**

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): मैं सरकार का ध्यान अपनी लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें दो जिले नुआपड़ा और कालाहांडी है। दोनों ही जिले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। मेरा निवेदन यह है कि जिला कालाहांडी में राहुल-उतई नदी के संगम पर कोई डैम नहीं है। राहुल-उतई नदी के संगम पर मीडियम डैम का डी.पी.आर वन मंजूरी के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। यदि उक्त नदी पर डैम बनाने के लिए वन मंजूरी मिलती है तो इसका लाभ सीधा कालाहांडी जिले के रामपुर मदनपुर और करलामुंडा ब्लॉक के साथ-साथ जिला बोलांगीर के गुडवेला ब्लॉक के किसानों को भी मिलेगा। बोलांगीर भी एक आकांक्षी जिला है। वन मंजूरी होने से किसानों के खेतों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और किसान साधन संपन्न होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। इन सभी ब्लॉक के किसान कृषि पर निर्भर करते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द वन मंजूरी के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि डैम बनाया जा सके और किसानों की फसल को सिंचाई की सुविधा मिल सकें।

(x) Need to set up a Buddhist Culture and Heritage Conservation Centre and also a Convention Centre in Siddharthnagar district.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने अपने जीवन के पहले 29 वर्ष बिताए थे। लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा सिद्धार्थनगर जिले को 112 आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। सिद्धार्थनगर के लोग आकांक्षी जिले के रूप में सिद्धार्थनगर की पहचान करने और जिले में विकास और समृद्धि लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साथ ही दृष्टि और नेतृत्व प्रदान करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बहुत आभारी हैं। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु बौद्ध तीर्थयात्रा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और हर साल कई बौद्धों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी कपिलवस्तु आते हैं। इसलिए, बौद्ध तीर्थयात्रियों और अन्य उद्देश्यों की सुविधा के लिए कपिलवस्तु में बौद्ध संस्कृति और विरासत संवहन केंद्र स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। बोध महोत्सव, बौद्ध सम्मेलन, एसोसिएशन ऑफ बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर्स (एबीटीओ) जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को निजी स्थान की तलाश करनी पड़ती है। कन्वेंशन सेंटर बनने से यह समस्या दूर हो जाएगी। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय विक्रेताओं के लिए व्यापार के अवसर भी प्रदान करेगा। बड़ी भागीदारी के लिए बड़े आध्यात्मिक और बौद्ध कार्यक्रम, व्यापारिक सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

(xi) Regarding crop insurance claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Churu Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री राहुल कस्वां (चुरु): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के अधीन चुरु, नोहर-भादरा, रावतसर (हनुमानगढ़) के अधीन खरीफ फसल वर्ष 2021 का बीमा क्लेम जारी करवाने की ओर दिलाना चाहूंगा। चुरु जिले के किसानों को खरीफ वर्ष 2021 का बीमा क्लेम भुगतान लगभग 200 करोड़ रुपये किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियमानुसार क्रोप कटिंग के आधार पर किसान वही भुगतान 500 करोड़ रुपये लेने के हकदार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नीति साफ कहती है कि क्रोप कटिंग के डाटा बीमा कम्पनी के अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी व किसान के समक्ष हस्ताक्षरों सहित लिये गये हो तो उस क्रोप कटिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने State Level Technical Committee में बीमा कम्पनी की शिकायत दर्ज कर ली, जो किसानों के साथ अनुचित व्यवहार है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि चुरु क्षेत्र के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा State Level Technical Committee के फैसले को रिवाइज करते हुए क्रोप कटिंग के आधार पर खरीफ फसल वर्ष 2021 का बीमा क्लेम जारी करवाने का श्रम कराया जाए।

(xii) **Regarding establishment of Post Office Passport Seva Kendra in Guna and Shivpuri in Madhya Pradesh.**

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तीन जिले अशोकनगर, गुना और शिवपुरी आते हैं जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है और इनमें से गुना को आकांक्षी जिलों की सूची में भी रखा गया है । भारत सरकार द्वारा 2014 से अब तक 400 से अधिक नए पासपोर्ट केंद्रों की स्थापना की गई है जिसमें गुना और शिवपुरी के लिए भी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को 2019 में स्वीकृति दी गयी थी । 3 वर्ष पश्चात भी गुना और शिवपुरी में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना के सन्दर्भ में कुछ व्यापक कार्य नहीं हुए हैं और मेरे क्षेत्र के निवासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए ग्वालियर, इंदौर या भोपाल तक यात्रा करनी पड़ती है और पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में विलंब होने के अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है । मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की जनता को पासपोर्ट सेवा केंद्र के अभाव में हो रही दिक्कत का निवारण करने हेतु गुना और शिवपुरी के लिए स्वीकृत पासपोर्ट सेवा केंद्रों की स्थापना के कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय उपयुक्त कदम उठाये और तत्काल प्रभाव से इनके निर्माण के काम को शुरू किया जाए जिससे उन्हें दूसरे जिलों तक यात्रा करने की आवश्यकता न पड़े ।

(xiii) Need to grant environment clearance to development projects in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency.

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): देश की विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े, अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों की विकास संबंधी अनेकों परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने की वजह से अधर में पड़ी रहने की वजह से विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है तथा पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने के परिणामस्वरूप विकास संबंधी निर्माण कार्यों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। इसके अलावा अनेक ऐसी भी विकास संबंधी परियोजनाएं हैं, जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के कड़े नियमों के चलते अधर में लटकी हुई हैं। इस संबंध में, मैं अपने संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली – चिमुर में स्थित आस्टी-आलमपल्ली - सिरोनचा (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353 - सी), जो जीर्णशीर्ण स्थिति में है तथा जिसके निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन वन (संरक्षण) अधिनियम में दिए गए कड़े प्रावधानों की वजह से इस 16 किलोमीटर लम्बे राजमार्ग का सी०सी० निर्माण नहीं हो पा रहा है तथा इसी प्रकार से मेरे संसदीय क्षेत्र में ही स्थित देवरी नगर पंचायत, जो दुर्गम आदिवासी अति पिछड़ा क्षेत्र है, में इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन (ई०एस०जेड०) की आड़ में उद्योग- धंधे स्थापित करने में बाधा आ रही है। मेरा माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र राज्य की विशेषतः आदिवासी और नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली - चिमुर की छोटी-बड़ी लंबित विकास संबंधी सभी परियोजनाओं को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में दिए गए प्रावधानों में विशेष परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान कर स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाएं।

(xiv) Regarding inclusion of femicide as an offence under the Indian Penal Code.

DR. T. SUMATHY(A)THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):

Violence against women isn't just an onslaught on their mind, body and soul; rather an expression of a misguided sense of supremacy men think they hold over women. Whether it is the incidents of strangulation and mutilation of a women in Delhi by her partner or the immolation of a 19-year-old in Jharkhand by her stalker; ghastly incidents of gendered violence are brought to light frequently.

This form of violence, referred to as femicide is conveniently eluded in the criminal justice system and not even recorded separately under the National Crime Records Bureau Reports. The Indian Penal Code doesn't include a comprehensive definition of femicide and loose references are found only in the context of dowry-related deaths and domestic violence.

Factors like associated stigmas and reluctance to report, all the more scream the need for authentic data collection, a precursor to developing effective policies. Globally, the significance of the issue was recognized after the United Nations called for counting of femicide cases. Thus, I implore the Government to initiate necessary action to include femicide in the India Penal Code and facilitate reliable data collection to aid effectual policy-making.

(xv) Regarding not to ban film/documentary on ideological differences.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Ministry of Information and Broadcasting issued direction to block the BBC documentary on 2002 Gujarat riots using 'emergency powers' under Information and Technology rules under the IT Act. The videos have been blocked under India's sovereign laws rules. Various youth organizations and student's unions in universities like JNU and Presidency screened the first episode of BBC documentary across India to lodge protest against the move to block it on social media and public viewing. I urge upon the government not to ban this or any film/documentary on ideological differences, since that would be against Freedom of Speech and Expression as guaranteed under the Constitution.

(xvi) Regarding release of coal levy to states.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Government of India have realised additional levy with respect to coal extracted from the prior allottees of 31 cancelled Schedule -II coal mines in various States. The additional Levy of Rs.295/- per M.T. has been imposed in terms of the provisions of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance 2014/Act, 2015. About Rs.560 crore paid by M/s HINDALCO Industries on account of Talabira, a Schedule -II Coal Block situated in the State, is a legitimate due of Odisha. Other States like Chhattisgarh and West Bengal have also put forth similar claims. The amount due has not been transferred to the State so far although the matter was taken up with Union Government earlier.

I would request to issue suitable advisory to the Ministry of Coal for release of the additional levy realised, to the respective State Governments at the earliest.

(xvii) Regarding laying of sewer lines under AMRUT Yojana in Jaunpur, Uttar Pradesh.

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Roads are being dug up from Olandganj to Line Bazaar in Jaunpur to lay sewer lines under the AMRUT Yojana. These areas are among the busiest in the city. This stretch caters to traffic from and to Diwani, Collectorate, schools, banks. Water and mud are lying all over the road making it difficult for people to walk. It also leads to traffic jams. Two wheelers slip and lead to accident. Work was to be completed by Oct 2021. Only 60 kms of sewer pipelines has been laid out of the targeted 169 kms. Work progressing is at snail's pace. Even after laying pipelines at some points, mud has been left like that only. Road have not been repaired. Pipes are lying broken at several places leading to waterlogging. Air pollution is being caused due to digging up of roads and Jaunpur's AQI is amongst the worst in the world. I urge upon the Government to look into the issues arising out of the laying of sewer lines under AMRUT Yojana in Jaunpur, Uttar Pradesh.

(xviii) Regarding water pollution in the backwaters of Khadakwasla dam.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): The backwaters of Khadakwasla dam has turned all grey and toxic from the gallons of untreated sewage waste that is discharged in it. The backwaters are the major source of drinking water for the Pune city and this ill-treated water is causing serious concerns for general public health. Not just human wastes, but waste released by small fabricators and powder coating workshops is also discharged untreated into the water body. Gram Panchayats are looking for solution but due to lack of resources to manage rising solid waste and population around the area there seems to be no solution. Pune Municipal Corporation too lacks efficient technology to effectively separate pollutants from water. The simple chlorine based technology which is currently used to treat water is inefficient in treating this chemically adulterated water. Areas like Dhairey, Sinhagad road, DSK colonies , Shivne almost upto Ujjani dam areas are seriously affected. I urge upon the Hon'ble Minister of Jal Shakti to take concrete steps and install efficient technology like advance plasma membrane technology at different stages of water purification till its final supply to the city.

माननीय सभापति: आप लोग कृपया बैठ जाइए ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग सहयोग कीजिए । It is very, very important.

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हम सबको ज्वाइंट सेशन में संबोधित किया है। ... (व्यवधान) उसके लिए जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होती है। इसलिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ज्वाइंट सेशन में महामहिम राष्ट्रपति जी का यह पहला भाषण है। ... (व्यवधान) इसलिए, मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग चर्चा कीजिए।... (व्यवधान) पार्लियामेंट चर्चा के लिए है। आप लोग चर्चा कीजिए। जब बजट सेशन शुरू होता है तो हमारी फर्स्ट प्रॉइयोरिटी राष्ट्रपति अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स की रहती है। ... (व्यवधान) इसलिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कृपया चर्चा शुरू कीजिए, गलत परम्परा मत डालिए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया चर्चा प्रारंभ होने दीजिए। आप जो भी विषय उठाना चाहते हैं, उसकी अनुमति होगी और चर्चा होगी।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please cooperate.

... (Interruptions)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी, 2023 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.06 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Friday, February 3, 2023/Magha 14, 1944 (Saka)*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.